

प्रेषक,

डॉ उमाकांत पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 23 अप्रैल, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सीजी-208/हो0गा0/2015/24, दिनांक-05.04.

2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु प्रावधानित मदों की निम्नांकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-106-सिविल रक्षा-03-स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)।

मद का नाम	धनराशि (हजार रुपये में)
01-वेतन	1167
02-मजदूरी	67
03-महंगाई भत्ता	933
04-यात्रा व्यय	25
06-अन्य भत्ते	333
08-कार्यालय व्यय	33
09-विद्युत देय	167
10-जलकर/जल प्रभार	2
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छ	27
12-कार्यालय फर्नीचर	33
13-टेलीफोन पर व्यय	20
15-गाड़ियों का अनुरक्षण	67
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	200
17-किराया, उपशुल्क	33
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	13

19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	13
26-मशीनें और साज- सज्जा	40
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
31-सामग्री और सम्पूर्ति	133
42-अन्य व्यय	23
44-प्रशिक्षण व्यय	133
45-अवकाश यात्रा व्यय	17
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय	33
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	33
योग	3582 (रु0 पैंतीस लाख बयासी हजार मात्र)

- 2- उक्त धनराशि वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-490/XXVII(1)/2016, दिनांक-31.03.2016 की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।
- 3- जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।
- 4- बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
- 5- जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायें।
- 6- मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-106-सिविल रक्षा-03-स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या-490/XXVII(1)/2016, दिनांक-31.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति व निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन अलोटमेंट आई0डी0 संख्या-S1604060192 दिनांक-12.04.2016 द्वारा निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(डॉ उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 382/XX(5)/16-07(ना0सु0)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

2-वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

3-वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।

✓ 4-एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
संयुक्त सचिव।